

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

**Need for district-wise evaluation of New Green Field Airports, under regional connectivity scheme in Uttar Pradesh**

**डा. लक्ष्मीकांत बाजपेयी** (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, देश में अपरिचालित एवं अल्पपरिचालित हवाई अड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने तथा आम जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने हेतु नागर विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्क योजना 'उड़ान' (उड़े देश का आम नागरिक) शुरू की है। 'उड़ान' एक सतत योजना है, जिसके अंतर्गत और अधिक गंतव्य स्टेशनों तथा मार्गों को शामिल करने के लिए समय-समय पर बोलियों के चरण आयोजित किए जाते हैं। भारत सरकार ने राज्य सरकारों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण और सिविल एन्क्लेवों के मौजूदा परिचालित, अल्पपरिचालित हवाई अड्डों/हवाईपट्टियों के उद्धार हेतु 4,500 करोड़ रुपये के बजट का अनुमोदन भी किया है। इस योजना की शुरुआत के बाद से अब तक एक करोड़ से अधिक हवाई यात्रियों ने 'उड़ान' योजना का लाभ उठाया है। यह योजना देश में टियर-2 और टियर-3 शहरों के बीच संपर्क पर ध्यान केंद्रित करती है। हमने यह भी देखा है कि कोविड महामारी का इस योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कुछ मार्गों के परिचालन में देरी तथा मार्गों पर प्रचालन बंद करने के कारण भी इस योजना की गति पर फर्क पड़ा है। अवार्ड किए गए मार्गों पर प्रचालनों की निरंतरता का कायम न रहना भी एक मुख्य कारण देखा गया है, साथ ही चयनित एयरलाइन प्रचारकों का तैयार न होना भी विलम्ब का एक कारण है।

अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय नागरिक विमानन मंत्री जी से निवेदन है कि इस योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले नए ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों और उत्तर प्रदेश राज्य में बनाए जाने वाले नए ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों की स्थिति का जिलेवार मूल्यांकन करके उनमें सुधार लाया जाए। साथ ही देश भर के सभी हवाई अड्डों पर जो मंत्रालय द्वारा चयनित किए गए हैं, उन पर

लम्बित कार्य और औपचारिकताओं को पूर्ण करके उड़ान आरम्भ की जायें, जिससे कि देश का आम नागरिक भी अपने शहर से उड़ान भरने का आनन्द ले सके।

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, I associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Shri Elamram Kareem — Not present. Shri Shanmugam.

#### **Need for time-bound completion of Vikravandi-Kumbakonam National Highway project in Tamil Nadu**

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Sir, Vikravandi-Kumbakonam National Highway Project, namely, NH-45C, was proposed and started during the UPA regime, keeping in view the demand for hassle-free transport in the Delta Region. After feasibility report and Budget grants, the project work was started in March 2018, and it is still going on at snail's pace. In some sections, the road conditions are very poor and the people are facing a lot of inconveniences while travelling. For example, in Koliyanpur-Pinnalur section, the road conditions are very bad. Coleroon, Kollidam river bridge in Annaikarai collapsed during construction stage and, therefore, immediate action should be taken to construct the bridge and reinforce the strength of the bridge. Vikravandi-Sethiathopu section of NH-45C is not getting completed, so also the Cholapuram-Thanjavur section. People are facing a lot of difficulties in commuting in these places. Different contractors are taking up this project and the execution work is going very slow. I would request the hon. Minister for Road Transport and National Highways to direct the NHAI authorities to closely monitor these projects and should ensure that the road construction projects in these sectors